भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधीन रुग्ण इकाइयां

2074. **श्री राम सिंह राठवा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत इकाइयों के रुग्ण होने के आंतरिक कारणों का पता नहीं लगाया गया है ; और

(ख) 31 दिसम्बर, 1993 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के अधीन कितनी रुग्ण इकाइयां थीं और उन पर कितनी धनराशि ऋण के रूप में बकाया थी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि औद्योगिक एककों की रुग्णता के कारण प्रत्येक मामले में अलग-अलग होते हैं । सहायता प्राप्त एककों पर अनुवर्ती कार्रवाई और मानीटरिंग के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, प्रारम्भिक रुग्णता के आन्तरिक कारणों का पता लगाता है, जो सामान्यतः प्रबंधकीय कमजोरियों, समय और लागत में वृद्धि, पुरानी प्रौद्योगिकी, श्रमिक समस्याओं आदि से सम्बद्ध होती है । आगे और खराबी से बचने के लिये और एकक की अर्थक्षमता को पुनः स्थापित करने के लिये विभिन्न उपाय किये जाते हैं ।

(ख) मार्च, 1993 के अन्त की स्थिति के अनुसार (अद्यतन उपलब्ध) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पोर्ट-फोलियो में 375 रुग्ण एकक शामिल थे और इनमें कुल 1344 करोड़ रुपये की बकाया रकम ग्रस्त थी ।

विदेशी ऋणों की अधिकतम सीमानिर्धारित करना

2075. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी ऋणों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो, उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) से (ग) सरकार देश की विदेशी ऋण देयताओं के विषय में सचेत है और देश की ऋण ग्रस्तता के स्तर और ऋण शोधन प्रभार के संभाव्य बोझ पर निरंतर निगाह रखती है । विदेशी ऋण हेतु समझौता करते समय वह बात हमेशा ध्यान में रखी जाती हैं कि देश का ऋण बोझ और ऋण शोधन देयतायें इस प्रकार के ऋणों का शोधन करते समय अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक न हों । सरकार ने अल्पावधि स्थिरीकरण सहित दीर्घावधि पुर्ननिर्माण का लक्ष्य रखते हुए आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम पहले ही प्रारंभ कर दिया है । इन सुधारों से देश को आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और हमारी निर्यात अर्जन क्षमता सहित हमारी विकास प्रक्रिया पुनर्जीवित होगी जिससे ऋणों की वापसी अदायगी की हमारी क्षमता बढ़ सकेगी और यह सुनिश्चित हो सकेगा कि ऋण शोधन प्रभार का बोझ इस प्रकार के ऋणों का शोधन करते समय अर्थव्यवस्था की क्षमता से अधिक नहीं होगा ।

सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिये कार्रवाई योजना

2076. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से